

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग-01
संख्या: 372/XX-1/2016-7(14)2006
देहरादून, दिनांक 29 मार्च, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में Prakash singh vs. Union of India(2006 8 SCC 1) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2006 में दिये गये directions का अनुपालन करते हुए उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2008) दिनांक 04 जनवरी, 2008 को प्रख्यापित की गयी है, जिसमें राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का प्राविधान है।

2- रिट पिटीशन संख्या: (C) 317/2013, सरफराज मुल्ला एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में राज्य की ओर से मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल किये गये प्रतिशपथ पत्र में उक्त वर्णित उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2008) की प्रति संलग्न करते हुए उसके प्राविधानों से मा0 न्यायालय को अवगत कराया गया है।

3- रिट पिटीशन संख्या: (C) 317/2013, सरफराज मुल्ला एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य की मा0 उच्चतम न्यायालय में पैरवी किये जाने हेतु आबद्ध किये गये एडवोकेट-ऑन-रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, श्री राजीव नन्दा द्वारा राज्य को यह सूचित किया गया कि उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के वर्तमान प्राविधान से Prakash singh vs. Union of India(2006 8 SCC 1) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2006 में दिये गये directions का अनुपालन पूर्ण रूपेण नहीं हो रहा है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में यह अपेक्षा की गयी कि विषयगत वाद में Prakash singh vs. Union of India(2006 8 SCC 1) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2006 में दिये गये directions का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की ओर से मा0 उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल की जाय।

4- विषयगत प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 02.03.2016 को एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें अन्य अधिकारियों सहित प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी उत्तराखण्ड शासन भी सम्मिलित हुए। इस महत्वपूर्ण बैठक में Prakash singh vs. Union of India(2006 8 SCC 1) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2006 में दिये गये directions के शीर्षक Police Complaints Authority में दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत निम्न निर्णय लिये गये:-

1. मा0 उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार जिला स्तर पर जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाये जाने पर निर्णय हुआ, किन्तु यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड जैसे छोटे राज्य को देखते हुए तथा इस राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था एवं रेगुलर पुलिस व्यवस्था प्रचलित होने के कारण कुमाऊँ मण्डल के जिलों के लिए जिला नैनीताल के हल्द्वानी में एक District level Complaints Authority बना दी जाय तथा इसी प्रकार गढ़वाल मण्डल के जिलों के लिए जिला देहरादून के, देहरादून में भी एक District level Complaints Authority बना दी जाय तथा इसमें Chairperson एवं सदस्यों के चयन हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शक सिद्धांत का ही अनुसरण किया जाय।
2. उक्त क्रम में ही उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम में प्राविधानित राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में प्राधिकरण के Chairperson एवं सदस्यों के चयन हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शक सिद्धांत का ही अनुसरण किया जाय।

3. उक्त प्रकार से गठित होने वाले जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण तथा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की अनुशंसा/संस्तुति को concerned authority के लिये binding कर दी जाय, किन्तु जिसके विरुद्ध अनुशंसा की जा रही है, वह अग्रेत्तर मा0 न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
 4. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण तथा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण field enquiries के लिए सी.आई.डी./इन्टेलीजेंस/विजीलेंस एवं अन्य जांच ऐजेंसियों से सेवानिवृत्त अधिकारियों को रख सकते हैं, सम्बन्धी प्राविधान भी उक्त प्राधिकरण में करा ली जाय।
 5. यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त उल्लिखित सभी निर्णयों के सापेक्ष प्रथमतः शासनादेश अथवा कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से आदेश पारित कर दिये जाय तथा कालान्तर में उक्तवत् पारित आदेश का समावेश उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम में संशोधन करते हुए अधिनियम में कर ली जाय।
 6. उक्त के अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त निर्णयों पर कार्यवाही से पूर्व पत्रावली न्याय विभाग को संदर्भित करते हुए इस विषय पर परामर्श प्राप्त कर लिया जाय कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित मार्गदर्शक सिद्धांत दिनांक 22.09.2006 के आलोक में उक्तानुसार लिये गये निर्णय की प्रतिपूर्ति करते हुए किस प्रकार से आदेश निर्गत किया जा सकता है, के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण परामर्श न्याय विभाग से प्राप्त कर लिया जाय एवं न्याय विभाग के परामर्शानुसार ही समुचित कार्यवाही की जाय।
- 5- उपरोक्त क्रम में न्याय विभाग से बहुमूल्य परामर्श प्राप्त करते हुए उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कार्यवाही करते हुए जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण तथा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश/directions दिनांक 22.09.2006 के अनुसार कार्यवाही कर लिये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य सरकार की ओर से प्रतिपूरक शपथपत्र मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दाखिल किया जा चुका है।
- 6- उपरोक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त रिट पिटीशन संख्या: 310/1996 प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश/directions दिनांक 22 सितम्बर, 2006 के अनुपालन में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण एवं राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण निम्न स्वरूप में गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण-

1. राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य होंगे।
2. राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष, मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही हो सकते हैं।
3. राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मा0 मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाये गये सेवानिवृत्त जजों के पैनल में से ही की जा सकती है।
4. राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, राज्य मानवाधिकार आयोग/लोकायुक्त/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किये गये नामों के पैनल से की जायेगी तथा राज्य मानवाधिकार आयोग/लोकायुक्त/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सदस्यों के चयन हेतु नामों का पैनल सेवानिवृत्त सिविल सर्वेन्ट्स/पुलिस

अधिकारी/अन्य विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारी तथा सिविल सोसाईटी से तैयार की जायेगी।

5. राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण अपर पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही करेगी।
6. राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण पुलिस से सम्बन्धित गम्भीर कदाचार यथा मृत्यु, गम्भीर चोट तथा पुलिस अभिरक्षा में बलात्कार आदि अन्य संगीन घटनाओं का संज्ञान लेकर जांच करेगी तथा विभागीय/आपराधिक कार्यवाही की संस्तुति करेगी।

2) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण-

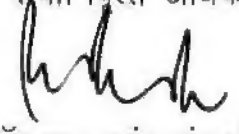
1. उत्तराखण्ड के छोटा राज्य होने तथा इस राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था एवं रेगुलर पुलिस व्यवस्था प्रचलित होने को दृष्टिगत रखते हुए कुमाऊँ मण्डल के जिलों के लिए जिला नैनीताल के हल्द्वानी में जिला शिकायत प्राधिकरण गठित की जायेगी। इस प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार कुमाऊँ मण्डल के समस्त जिलों अर्थात् नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, अल्मोडा, बागेश्वर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ में नियत किया जाता है।

उक्त क्रम में ही गढ़वाल मण्डल के जिलों के लिए जिला देहरादून के देहरादून में भी जिला शिकायत प्राधिकरण गठित की जायेगी। इस प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार गढ़वाल मण्डल के समस्त जिलों अर्थात् देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी एवं उत्तरकाशी में नियत किया जाता है।

2. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे।
 3. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर सेवानिवृत्त जिला जज को नियुक्त किया जायेगा।
 4. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मा० मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित मा० उच्च न्यायालय के मा० न्यायाधीश द्वारा सुझाये गये नामों के पैनल में से की जा सकती है।
 5. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, राज्य मानवाधिकार आयोग/लोकायुक्त/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किये गये नामों के पैनल से की जायेगी तथा राज्य मानवाधिकार आयोग/लोकायुक्त/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सदस्यों के चयन हेतु नामों का पैनल सेवानिवृत्त सिविल सर्वेन्ट्स/पुलिस अधिकारी/अन्य विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारी तथा सिविल सोसाईटी से तैयार की जायेगी।
 6. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण पुलिस उपाधीक्षक एवं उससे निम्न स्तर के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर जांच करेगी।
 7. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण गम्भीर कदाचार, जो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, गम्भीर चोट अथवा बलात्कार के प्रकरणों के अतिरिक्त पुलिस कर्मियों द्वारा जबरन वसूली, भूमि एवं भवनों पर अवैध कब्जे आदि तथा अन्य गम्भीर घटनाओं, जिसमें पद का दुरुपयोग परिलक्षित हो की जांच करेगी तथा विभागीय/आपराधिक कार्यवाही की संस्तुति करेगी।
- 3) उपरोक्तानुसार गठित राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा किसी अपचारी पुलिस कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में जो अनुशंसा की जायेगी, वह राज्य सरकार पर बाध्यकारी होगी अर्थात् उक्त प्राधिकरणों के द्वारा की गयी अनुशंसा के क्रम में अपचारी पुलिस कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उसे

नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए नोटिस देकर विधि अनुसार कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा सम्पादित की जायेगी। यदि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण अथवा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा किसी अपचारी पुलिस कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित अपचारी कार्मिक द्वारा उसे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के अनुसार सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की अनुशंसा के क्रम में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अपचारी कार्मिक के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के विरुद्ध भी अपचारी कार्मिक द्वारा सक्षम प्राधिकारी/सक्षम न्यायालय के समक्ष भी अपील की जा सकती है।

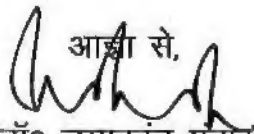
4) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण तथा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण field enquiries के लिए सी.आई.डी./इंटेलीजेंस/विजिलेंस एवं अन्य जांच एजेंसियों से सेवानिवृत्त अधिकारियों को आवश्यकतानुसार रखा जा सकता है।


(डॉ० उमाकांत पवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 372 (1)/XX(1)-2016-7(14)2006, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, न्याय एवं प्रमुख विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव एवं विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य प्रधान सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. अपर सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय एवं निर्देश के साथ कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण तथा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के लिए किये जा रहे उक्त प्राविधान का समावेश उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम में संशोधन करते हुए अधिनियम में कर ली जाय। इस हेतु यथावश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर लें।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
7. रजिस्ट्रार जनरल, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8. सचिव, मानवाधिकार आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
10. सहायक निबन्धक, मानवाधिकार आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
12. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
13. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुडकी(हरिद्वार) को इस आशय के साथ कि असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-भाग-4, खण्ड(ख) में उक्त को प्रकाशित को कराये तथा कार्यालय ज्ञाप की मुद्रित 100 गजट प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


(डॉ० उमाकांत पवार)
प्रमुख सचिव